organisations. So, in order to meet this shortage, Government is planning to have a third dairy. Apart from that, the UP Milk Co-operative Federation has also proposed to set up a dairy with an installed capacity of 2 lakh litres per day at Noida and that plant will supply milk to the peripheral areas of Delhi.

श्री राम नरेश यादव : महोदय, क्योंकि डी०एम०एस० की तरफ से 4.83 लीटर प्रति दिन सप्लाई होता है तथा मदर डेयरी की तरफ से 3.82 लाख लीटर प्रति दिन सप्लाई होता है, सरकार यह कह रही है कि हम दूसरी डेरी बनाने की बात सोच रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना को स्थान में रखते हुए, जो आने वाली है, उसमें आपकी क्या योजना है, कहां तक इसको आप पूरा कर सकेंगे, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

SHRI K. C. LENKA: Sir, Mother Dairy supplies 5.44 lakh litres of milk daily instead of 3.82 lakhs. These two agencies are procuring milk from the co-operative and federations in the nearby States. In order to meet the requirement of milk, Government is planning during the Eighth Five Year Plan to expand the production of milk in the peripheral areas so that sufficient milk can come and these agencies can distribute it to the Delhi people.

श्री संघ प्रिय गौतम : धान्यवर, दिल्ली की सफाई के नाम पर यहां पर पहले जो लोग डेरी करते थे और भैंसे रखते थे वह अब यहां से खाली करवा दिया गया है और दिल्ली के आसपास के जिलों से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में दूध यहां आता है । उसमें कई तरह का दूध आता है, मिश्रित दूध आता है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के आस-पास के गांवों में यह डेयरी को डिवैलप करने के लिए, भैंसें अधिक पालने के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव वह रखते हैं जिससे दिल्ली को ताजा, सही और समय पर दूध मिल सके ?

MR. CHARMAN: Question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Withdrawal of free local telephone facilities to passengers at airports

*124. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that free local telephone facility provided to passengers at airports has been withdrawn; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The free local-call telephone facility provided by Department of Telecommunications at Atirports has been withdrawn with effect from 1st October, 1991. It is considered that provision of such a free telephone facility at the Airport by Department of Telecom is not justified. Pay phones, however, have been provided at the Airports.

National edible oil grid

*125. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a national edible oil grid;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) to what extent is it likely to reduce the present high prices and shortage of edible oils in the market?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Through the agency of the National Dairy Development Board, it is planned to link major oilseed producing

areas with the demand centres by establishing storage capacities and packaging stations in different parts of the country. It is also planned to develop an economical system for movement of oil and oilseeds from surplus to deficit areas. These measures will significantly help to ease the present pressures on edible oil availability and prices.

तिलहन उत्पादन-कार्यक्रम

*126. **श्री राधाकिशन मालवीय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन राज्यों को समय पर अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार, राज्य सरकारों को आदानों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का भी विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 18 महत्वपूर्ण तिलहन उत्पादक राज्यों में लागू किया जा रहा है । अच्छी क्वालिटी के बीजों का उत्पादन और वितरण इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है ।

बीजों का अवस्थावार उत्पादन विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है । प्रजनक बीज का उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रणाली की मदद से किया जा रहा है । आधारी बीज का उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्य बीज निगम तथा राज्य के कृषि विभागों द्वारा अपने फार्मों में किया जाता है। प्रमाणित बीज का उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य बीज निगमों द्वारा आयोजित किया जाता है ।

अच्छी क्वालिटी के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी आवश्यकता की समीक्षा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हर खरीफ तथा रबी मौसम से पहले कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में की जाती है। इन सम्मेलनों में राज्यीय एजेंसियों, राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम के कार्यकलापों में ताल मेल बैठाया जाता है । राज्यों को अपने निश्चित मांग पत्र काफी अग्रिम रूप से राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम को प्रस्तुत करने होते हैं ताकि वे राज्यीय एजेंसियों के कार्यक्रमों को पर्याप्त रूप से पूरा कर लें ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

Irrigation Projects

*127. SHRI RAM JETHMALANI:

SHRI RANJIT SINGH:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of 264 irrigation projects which were proposed to be constructed during the Seventh Five Year Plan period only 50 per cent of the projects could be completed during that period;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative what is the exact number of irrigation projects which have been completed so far;

(c) what was the targetted irrigation potential for generation during this period and what was the actual achievement; and

(d) what was the percentage of irrigation potential utilised during the last year of the Seventh Five Year Plan?